भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

जुलाई, 2021 के लिए मासिक सारांश

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73 वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्य के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. जुलाई 23, को 2021'ग्राम सभा को जीवंत बनाना' विषय पर चर्चा के लिए सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में राज्यों के पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान इस विषय पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए अवधारणा पत्र की सामग्री पर विचारविमर्श विचार किया गया।-

2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पुनरुद्धार पर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यशाला 22 जुलाई, 2021 को वस्तुतः सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आयोजित की / गई थी। कार्यशाला में पंचायती राज मंत्रालय, एनआईआरडी एवं पीआर, राज्य पंचायती राज विभाग और सभी राज्योंकर्मचारियों ने भाग लिया था। / केंद्र शासित प्रदेशों और एसआईआरडी के वरिष्ठ अधिकारियों/ आरजीएसए के कार्यान्वयन के अनुभव साझा करने और संशोधित स्कीम में और सुधारकरने के लिए फीडबैक के संबंध में विचारविमर्श किया गया।-

3. ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश वित्त मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों, पंचायती राज मंत्रालय को जारी किए गए हैं। इसके अनुपालन में, पंचायती राज मंत्रालय दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की दिशा में विभिन्न कार्रवाई करेगा।

4. स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में घर रखने वाले गृह मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के उद्देश्य से 26 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों नेभारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं (एमओयू) औरयोजना के कार्यान्वयन हेतु अन्य राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए चर्चा चल रही है। राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उपलब्धि/आधारभूत लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सभी राज्योंकेंद्रशासित प्रदेशों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और भारतीय सर्वेक्षण / -भी आयोजित की गई थी। कोविड (वर्चुअल कोन्फ्रेंस) विभाग के साथ नियमित बैठक19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों और मौसम की स्थितियों जैसे तेज हवाएं और बारिश आदि के बीच 52,970 गांवों में ड्रोन उड़ान और 37 जिलों में ड्रोनसर्वेक्षण पूरा हो गया है।-

5. पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को (पीएफएमएस) अपनाने के लिए राज्योंको सख्ती से राजी कर रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय राज्यों के साथ ईग्राम - साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत के पंजीकरण के लिए प्रयास कर -स्वराज पर खाता बंद करने के साथ के लिए 21-2020 है। वर्ष रहा प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने अपनी मासिक किताबें बंद कर दी हैं और 93 %88ग्राम पंचायतों ने अपनी वार्षिक पुस्तकें बंद कर दी हैं। चालू वर्ष अर्थात वर्ष में 22-2021 %73 ग्राम पंचायतों ने जुलाई, हैं। के अंत तक अपनी मासिक पुस्तकें बंद कर दी 2021

6. 2,25,482 पंचायती राज संस्थाएँ ईपर आ चुकी (ईजीएसपीआई) पीएफएमएस इंटरफेस-ग्राम स्वराज- हैं। जुलाई, 2021 में 1,04, ओं नेपंचायती राज संस्था 775XVवें वित्त आयोग अनुदान के व्यय के लिए ईजीएसपीआई का उपयोग करते हुए ऑनलाइन लेनदेन किया है।

.7 पंचायती राज स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में; एमओपीआर ई- ग्रामस्वराज में रसीद प्रविष्टियों को स्वचालित रूप से कैप्चर करने के लिए'पीएफएमएस के साथ राज्य ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन' की प्रक्रिया में है। जुलाई, 2021 तक 21 राज्यों ने स्टेट ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन के इस अभ्यास को पूरा कर लिया है।

.8 साथ ही, जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए; मंत्रालय ने ईपंचायत - ऑडिटऑनलाइन शुरू किया है। यह पंचायत - के तहत एक एप्लिकेशन (एमएमपी) मिशन मोड परियोजना लाइन ऑडिट की सुविधखातों के ऑना देता है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी

रिकॉर्ड करता है। वर्ष 2019-20 के लिए 27 राज्यों ने (केरल सहित) लेखा परीक्षकों का पंजीकरण (6,765 लेखा परीक्षक पंजीकृत और (14वें वित्त आयोग के खातों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा योजना)1,16,202 ग्राम पंचायतें की तैयारी शुरू कर दी है। (26 राज्यों ने ग्राम पंचायत) उपयोगकर्ता (ऑडिटी)2,27,749 ऑडिटी (बनाना शुरू कर दिया है।26 राज्यों ने आवेदन पर टिप्पणियों)8,67,705 टिप्पणियां को (भी दर्ज किया है और 24 राज्यों ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट)78,543 रिपोर्ट तैयार की है। वर्ष (2020-21 के लिए 30,569 ग्राम पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा योजना तैयार की गई है।

.9 तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना के तहत करोड़ रुपये की धनराशि जारी 122.97 की गई है।

10. पंचायती राज मंत्रालय ने मार्च श्रीधरन .एन .में डॉ 2021, निदेशक, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति का अधिदेश ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (आरएडीपीएफआई)दिशानिर्देश, में आवश्यक 2017 के बाद से कई विकास हुए हैं। समिति ने मसौदा 2017 अद्यतनीकरण का सुझाव देना है क्योंकि 2021 - आरएडीपीएफआईदिशानिर्देश प्रस्तुत किए हैं।

11. जून, में 2021, पंचायती राज मंत्रालय ने डॉ एस .एस मीनाक्षीसुंदरम, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव और अध्यक्ष सलाहकार (आरडी), एनआईएएस, भारतीय विज्ञान संस्थान , बैंगलोर की अध्यक्षता में 'आरएडीपीएफआई दिशानिर्देश, 2021' की जांचमंत्रालयी समिति का गठन -समीक्षा करने के लिए एक अंतर/ किया। आईएमसी के अन्य सदस्यों में डॉश्रीधरन .एन ., निदेशक, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल (एमपी), सदस्य सचिव; सलाहकार प्रभारी पंचायती राज, नीति आयोग; संयुक्त सचिव ए), एल एवं ई (जन प्रभारीशहरी नियो, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; रुर्बन मिशन के प्रभारी संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय; श्री केसेठी .एस., संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय संयोजक हैं। आरएडीपीएफआई दिशानिर्देश, आयोजित की गई को 22.07.2021 को अंतिम रूप देने के लिए आईएमसी की पहली बैठक 2021 थी।

. 12 स्थानिक योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

दिनांक 27 जुलाई, 2021 को, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज मंत्रालय और बीआईएसएजीएन के बीच - के स्थानिक योजना से संबंधित एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन अनुसार, पंचायती राज मंत्रालय की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

I. स्थानिक योजना के लिए पंचायती राज ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कार्य करना।

II. योजना के बाद के अमल प्रवर्तन सहित, स्थानिक योजना प्रक्रिया के पूरे जीवन चक्र में पंचायती राज संस्थानों की ऑन बोर्डिंग।

III. स्थानिक योजना से संबंधित नीति स्तर के कार्यक्रम/कार्य।

IV. राज्योंकेंद्र शासित प्रदेशों को वार्षिक जीपीडीपी तैयारी क/े साथ स्थानिक योजनाओं और स्थानिक योजनाओं को जीपीडीपी तैयारी के साथ एकीकृत करने के लिए सलाह देना और मार्गदर्शन करना।

V. ग्राम मानचित्र एप्लिकेशन, जीपीडीपी पोर्टल और पंचायती राज मंत्रालय के अन्य पोर्टलों से रूर्बन क्लस्टर स्थानिक योजना के स्थानिक योजना का एपीआई एकीकरण।

13. अधिकांश राज्यों में कोविड -19 महामारी की स्थिति को आसान बनाने के साथ, राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों / आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नई परामर्शिका जारी की गई। को पंचायती राज मंत्री के निर्देश के अनुसरण में, राज्यों को सलाह दी गई थी कि आने वाले सप्ताहों में और अगस्त, 2022 तक उत्सव गतिविधियों के आयोजन और निगरानी के लिए पंचायती राज संस्थाओं को समर्पित आयोजन समिति का गठन करने की सलाह दी जाए।

.14प्रत्येक स्तर पर 75 बीकन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक राष्ट्रीय ओरिएंटेशन वेबिनार एकेएएम के हिस्से के रूप में 06.07.2021 को आयोजित किया गया था जिसमें सभी राज्य सरकार के पंचायती राज विभागों और बीकन पंचायतों के पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुखों ने भाग लिया था।

.15पंचायती राज मंत्री के निर्देश पर, मंत्रालय ने ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग के साथ बैठक की ताकि उन गतिविधियों की पहचान की जा सके जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग और डीओएलआर द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह लंबे कार्यक्रम के तहत संयुक्त रूप से आयोजित किया जा सकता है और तदनुसार समान हितों वाली 12 गतिविधियों की पहचान की गई।

.16आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 'मेरा मान मेरा राष्ट्रगान' पहल को बढ़ाने के लिए राज्यों केंद्रशासित / प्रदेशों को परामर्शिका जारी की गई, जिसमें राज्यों द्वारा बड़ी संख्या में जनता को संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाए गए समर्पित लिंक पर राष्ट्रगान गाने और अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई थी।

17 दिनांक .15.08.2021 को 'मेरा गाँव, मेरी धरोहर प्रोजेक्ट के शुभारम्भ' पर विशेष गतिविधियाँ और 15.08.2021 से शुरू होने वाले वर्ष भर का 'स्मृति समारोह' और 'एक मंत्रालय एक सप्ताह :' आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विस्तृत गतिविधियों की कार्य योजना तैयार की गई और संस्कृति मंत्रालय और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया गया। /

18 दिनांक .02.08.2021 को डैशबोर्ड को लाइव करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव की निगरानी के लिए समर्पित डैशबोर्ड के लिए कार्रवाई पूरी की गई।

19 दिनांक .1 जुलाई, 2021 को मंत्रालय के पास 41 शिकायतें याचिकाएं लंबित थीं और/जुलाई माह के दौरान 309 (अर्थात 287 ऑनलाइन +22 वास्तविकशिक (ायतें याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। कुल/350 (जुलाई में प्राप्त 309 + पिछले महीने से 41 अग्रेषित में से (300 शिकायतों याचिकाओं का जुलाई में निपटारा किया गया / और50 शिकायतों याचिकाओं /को 1 अगस्त, 2021 को आगे बढ़ाया गया।

.20जुलाई, 2021 के दौरान, ईऑफिस प्रणाली- में 146 ईफाइलें खोली गईं-, जो महीने के दौरान खोली गई कुल फाइलों का 100% है।

Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of July, 2021

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram SwarajAbhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1.. A VC meeting was held with senior officials of Panchayati Raj Department of States under the Chairmanship of Secretary, Panchayati Raj to discuss on the subject of 'Making Gram Sabha Vibrant' on 23rd July, 2021. During the meeting content of the concept paper prepared by the Ministry of Panchayati Raj on the subject were deliberated upon.

2. A National Workshop under the chairmanship of Secretary, Ministry of Panchayati Raj on Revamping of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan was held virtually with all States/UTs on 22nd July, 2021. The workshop was attended by Senior officers/ Officials of MoPR, NIRD&PR, State Panchayati Raj Departments and SIRDs of all States/ UTs. The deliberations were held regarding experience sharing of the

implementation of RGSA and feedback for further improvement in the revamped scheme.

3. Operational Guidelines for implementation of Fifteenth Finance Commission Grants for Rural Local Bodies has been issued by the Ministry of Finance to all the States, Ministry of Panchayati Raj (MoPR). MoPR will be taking various actions towards implementation of the Guidelines, in compliance of the same.

4. Under the SVAMITVA Scheme aiming to provide the 'Record of Rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of Property cards to the Property owners, 26 States/UTs have signed memorandum of understanding (MoU) with the Survey of India for the implementation of Scheme and discussions are on-going with other States for signing of MoU. Milestone based targets are being set for Sates/UTs. Further, regular meeting (VCs) with States and SoI for implementation of Scheme in all States/UTs were also held. Amidst restrictions imposed due to COVID-19 pandemic and weather conditions like high winds and rainfall etc., drone flying has been completed in 52,970 villages and drone-survey completed in 37 districts.

5. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing with States for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS.For the year 2020-21, 93% of the GPs have closed their month books and 88% of the GPs have closed their year books. In the current year i.e. 2021-22, 73% GPs have closed their month books as by end of July 2021.

6. 2,25,482 PRIs have on-boarded eGramSwaraj-PFMS Interface (eGSPI). In the month of July 2021- 1,04,775 PRIs have transacted online using eGSPI for the expenditure incurred XV Finance Commission Grant.

7. Towards strengthening the accountability and transparency at the PRI level; MoPR is in the process of 'Reverse Integration of State Treasury system with PFMS' to capture the receipt entries automatically in eGramSwaraj. By July 2021, 21 States have completed this exercise of reverse integration of State treasury system.

8. Also, for strengthening the transparency and accountability at grassroots level; the Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts and records detailed information about internal and external audit. For the year 2019-20, 27 (including Kerala) State have started registration of Auditors (6,765 Auditor registered) and preparation of Audit Plan (of 1,16,202GPs) for Auditing 14th Finance Commission accounts. 26 States have started creating GP (Auditee) users (2,27,749 Auditees). 26 States have also recorded Observations (8,67,705 observations) on the application and 24 States have generated audit reports (78,543Reports). For the year 2020-21, audit plans have been prepared by 30,569 GPs.

9. Funds to the tune of Rs.122.97 Cr has been released under the scheme of Rashtriya Gram SwarajAbhiyantowards the approved Annual Action Plan of the states of Tamil Nadu and Uttar Pradesh.

10. Ministry of Panchayati Raj constituted a Committee in March 2021 under chairmanship of Dr. N. Sridharan, Director, School of Planning & Architecture, Bhopal, Madhya Pradesh. Mandate of the Committee is to suggest necessary updation in the Rural Area Development Plan Formulation and Implementation (RADPFI) Guidelines, 2017 as several developments have taken place since 2017. The Committee has submitted the Draft RADPFI - 2021 Guidelines.

11. In June, 2021, MoPR constituted an Inter-Ministerial Committee (IMC) chaired by Dr. S.S. Meenakshisundaram, IAS (Retd.), former Secretary (RD) and Chairman Advisor, NIAS, Indian Institute of Science (IISc), Bangalore, to examine/review the 'RADPFI Guidelines, 2021'. Other members of IMC are Dr. N. Sridharan, Director, School of Planning & Architecture, Bhopal (MP), Member Secretary; Advisor in-charge

Panchayati Raj, NITI Aayog; Joint Secretary (A, L&E) in-charge of Urban Planning, Ministry of Housing & Urban Affairs; Joint Secretary in-charge of Rurban Mission, Ministry of Rural Development; Shri K.S. Sethi, Joint Secretary,Ministry ofPanchayati Raj, Convenor. The first meeting of the IMC was held on 22.07.2021 to finalise the RADPFI Guidelines, 2021.

12. Signing of MoU related to Spatial Planning

On 27th July, 2021, a tripartite Memorandum of Understanding (MoU) related to Spatial Planning between DoRD, MoPR and BISAG-N was signed. As per MoU, Roles and Responsibilities of MoPR are as under:

i. Working towards strengthening of the Panchayati Raj framework for Spatial Planning.

ii. On boarding of Panchayati Raj Institutions throughout the lifecycle of the Spatial Planning process, including the post plan enforcement.

iii. Policy level interventions related to Spatial Planning.

iv. Advise and guide States/UTs to integrate Spatial Plans with the annual GPDP exercise and vice-versa

v. API integration of Gram Manchitra application, GPDP portal and other portals of MoPR to Spatial Planning platform of Rurban cluster spatial planning.

13. With easing of Covid-19 pandemic situation in most of the States, fresh advisories to States/UTs issued for scaling up of activities in celebration of Aazadi Ka Amrut Mahostav (AKAM). In pursuance of direction of Minister, PR, the States were advised to further advise the PRIs to constitute dedicated Organizing Committee to organize and monitor the celebration activities in coming weeks and till August 2022.

14. A National Orientation Webinar for the elected representatives of 75 beacon PRIs at each level was held on 06.07.2021 as part of the AKAM which was attended to all State Government PR Departments and Heads of the PRIs of Beacon Panchayats.

15. On direction of Minister, PR, Ministry held meeting with Department of Rural Development and Department of Land Resources to identify activities that can be jointly orgnaised by MoPR, DoRD and DoLR under AKAM 75week long programme and accordingly 12 such activities with common interests were identified.

16. Advisory to States/UTs issued for scaling up the MeraMaanMeraRashtraGaan initiative under AKAM where by States were advised to encourage vast number of public to sing and upload the National Anthem on the dedicated link created by the Ministry of Culture.

17. Special activities on 'मेरा गॉव, मेरी धरोहर प्रोजेक्ट का लॉन्च' on 15.08.2021 and 'स्मृति समारोह' throughout the year beginning from 15.08.2021 and एक मंत्रालय: एक सप्ताह detailed activities action plan was drawn up under AKAM and communicated to MoC and States/UTs.

18. Action for dedicated Dashboard for monitoring the AKAM celebration completed to make the dashboard live on 02.08.2021.

19. There were 41 grievances/petitions pending with Ministry as on 1st July, 2021 and 309 (i.e. 287 online + 22 physical) grievances/ petitions were received during the month of July. Out of total 350 (309 received in July + 41 carried forward from last month), 300 grievances/petitions were disposed in July and 50 were carried forward as on 1st August, 2021.

20. During July 2021, 146 e-files were opened in e-office system which constitutes 100% of the total files opened during the month.

****